



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-आ.-24092020-221949
CG-MH-E-24092020-221949

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 376]
No. 376]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2020/आश्विन 2, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2020/ASVINA 2, 1942

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 8 सितंबर, 2020

सं.टीएएमपी/20/2010-केपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) की गांधीधाम टाउनशिप भूमि की वर्तमान दर संरचना की वैधता का, इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, विस्तार करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या: टीएएमपी/20/2010-केपीटी

दीनदयाल पत्तन न्यास

आवेदक

गणपूर्ति

- (i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(सितंबर, 2020 के 7 वें दिन पारित)

यह मामला दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) की गांधीधाम टाउनशिप भूमि की दर संरचना की वैधता के विस्तार के लिए डीपीटी द्वारा दायर प्रस्ताव से संबंधित है।

2. डीपीटी की गांधीधाम टाउनशिप भूमि की मौजूदा दर संरचना की वैधता का पिछला विस्तार डीपीटी के अनुरोध पर 29 नवम्बर, 2019 के आदेश संख्या टीएएमपी/20/2010-केपीटी के द्वारा 31 मार्च, 2020 तक अथवा डीपीटी द्वारा दायर किए गये प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित किराये की अधिसूचना के प्रभाव की तारीख तक, जो भी पहले हो, किया गया था।

3.1. चूंकि गांधीधाम टाउनशिप की वर्तमान दरों की वैधता 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो गई है, डीपीटी ने अब अपने 08 जून, 2020 के ईमेल के द्वारा इस प्राधिकरण से और 6 महीने की अवधि के लिए यानी 30 सितम्बर, 2020 तक वर्तमान दरों को प्रभारित करना जारी रखने का अनुरोध इस शर्त पर किया कि संशोधित दरें पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होंगी।

3.2. तत्पश्चात्, हमारे 07 जून, 2019 के पत्र के उत्तर में, डीपीटी ने 18 जून, 2020 के अपने ईमेल के द्वारा 29 फरवरी 2020 के अपने पत्र के अंतर्गत और फिर 17 जून, 2020 के एक और पत्र के द्वारा 01 जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर, 2018 तक की अवधि के लिये गांधीधाम टाउनशिप भूमि की दरों के संशोधन के लिये उनके 07 अप्रैल, 2016 के मूल पत्र के द्वारा भेजे गये प्रस्ताव का अनुमोदन चाहा है, जैसा कि डीपीटी बोर्ड ने 12 फरवरी 2016 के अपने संकल्प संख्या 140 द्वारा अनुमोदित किया था। इस संबंध में, डीपीटी को हमारे 23 जुलाई, 2020 के पत्र संख्या टीएएमपी/25/2016-केपीटी के द्वारा सूचित किया गया कि डीपीटी का 07 अप्रैल, 2016 का प्रस्ताव पोत परिवहन मंत्रालय के 02 अगस्त, 2016 के पत्र के फलस्वरूप हमारे 21 जुलाई, 2017 के आदेश संख्या टीएएमपी/25/2016-केपीटी के द्वारा पहले ही बंद कर दिया गया है और संबंधित संचिका भी बंद की जा चुकी है। उक्त आदेश बताता है कि डीपीटी से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसे नया मामला समझा जायेगा। अतः, डीपीटी से अनुरोध है कि वह गांधीधाम टाउनशिप भूमि की दर संरचना के संशोधन के लिये लागू भू-प्रबंधन नीति दिशानिर्देश, 2015 के अंतर्गत अपना प्रस्ताव दायर करे ताकि यह प्राधिकरण संबंधित हितधारकों के साथ नई परामर्श प्रक्रिया आरम्भ कर सके।

3.3. डीपीटी द्वारा प्रस्ताव दायर करने और मामले की प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा। चूंकि गांधीधाम टाउनशिप भूमि की दर संरचना 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो गई है और चूंकि 30 सितंबर 2020 नजदीक आई है, यह प्राधिकरण गांधीधाम टाउनशिप भूमि की वर्तमान दर संरचना को उसकी समाप्ति कि तारीख से मौजूदा दर संरचना की वैधता को 31 दिसंबर, 2020 तक अथवा डीपीटी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित पट्टा किरायों की अधिसूचना की तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तार करने के लिए इच्छुक है।

4.1. सरकार द्वारा जारी भूमि नीति दिशानिर्देश 2010 (जिसके आधार पर गांधीधाम टाउनशिप भूमि की दर संरचना अप्रैल, 2012 में नियत की गई थी) अनुबद्ध करते हैं कि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पट्टा किरायों में 2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि तब तक होती रहेगी जब तक उनका संशोधन इस प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जाता। इस प्राधिकरण द्वारा अप्रैल, 2012 में अनुमोदित आदेश में भी इस संबंध में विशिष्ट शर्त निर्धारित की गयी थी। यह शर्त पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी भूमि प्रबंधन नीति दिशानिर्देश, 2015 में भी अभिभावी है। चूंकि मौजूदा पट्टा किराया अनुसूची में जब तक पट्टा किरायों में इस प्राधिकरण द्वारा संशोधन नहीं किया जाता तब तक पट्टा किरायों में 2 प्रतिशत की दर पर वार्षिक वृद्धि सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है। इसलिए 2 प्रतिशत की दर पर वार्षिक वृद्धि गांधीधाम टाउनशिप भूमि की दर संरचना की विस्तारित अवधि के दौरान लागू रहेगी।

4.2. फिर भी, इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि 2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ वर्तमान परिदृश्य में मौजूदा पट्टा किरायों का विस्तार निर्वात से बचने के लिए एक अंतरिम व्यवस्था है। इस संबंध में डीपीटी द्वारा दायर प्रस्ताव के आधार पर गांधीधाम टाउनशिप के लिए निर्धारित पट्टा किराया को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाना होगा, जैसाकि डीपीटी ने अनुरोध किया है।

5. परिणाम में और सामूहिक विचार-विमर्श के उपरांत ऊपर बताये गए कारणों से यह प्राधिकरण, गांधीधाम टाउनशिप भूमि की मौजूदा दर संरचना की वैधता को उसकी समाप्ति की तारीख से 31 दिसंबर, 2020 तक अथवा डीपीटी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित पट्टा किरायों की अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तार करता है।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-3/4/असा./230/2020-21]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th September, 2020

No.TAMP/20/2010-KPT.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing rate structure for Gandhidham Township land of Deendayal Port Trust (DPT) as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No.TAMP/20/2010-KPT

Deendayal Port Trust

Applicant

QUORUM:

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 7th day of September 2020)

This case relates to a proposal filed by Deendayal Port Trust (DPT) for extension of the validity of the rate structure for Gandhidham Township Land of DPT.

2. The validity of the existing rate structure for Gandhidham Township Land of DPT was last extended based on the request of DPT vide Order No.TAMP/20/2010-KPT dated 29 November 2019 from the date of expiry till 31 March 2020 or till the date of effect of notification of the revised lease rentals based on the tariff proposal filed by the DPT, whichever is earlier.

3.1. Since the validity of existing rates of Gandhidham Township expired on 31 March 2020, the DPT has, vide its email dated 08 June 2020 has requested this Authority to allow it to continue to charge at the existing rates for a further period of 6 months i.e. upto 30 September 2020, subject to condition that revised rates will be made applicable with retrospective effect.

3.2. Subsequently, in response to our letter dated 7 June 2019, the DPT has, vide its email dated 18 June 2020 under cover of its letter dated 29 February 2020 and another letter dated 17 June 2020 sought approval to the proposal forwarded by the DPT vide its original letter dated 7 April 2016 for revision of rates for Gandhidham township for the period from 1 January 2014 to 31 December 2018 as approved by the DPT Board vide Resolution No.140 of 12 February 2016. In this regard, the DPT has been informed vide our letter No.TAMP/25/2016-DPT dated 23 July 2020 that the DPT proposal dated 7 April 2016 has already been closed vide Order No.TAMP/25/2016-KPT dated 21

July 2017 consequent to MOS letter dated 02 August 2016 and the concerned file has also been closed. The said Order stated that revised proposal to be filed by the DPT shall be treated afresh. Hence DPT has been requested to file the proposal for revision of rate structure of Gandhidham Township as per applicable Policy Guidelines for Land Management 2015 to enable TAMP to initiate a fresh consultation process with concerned stakeholders.

3.3. Filing of proposal by the DPT and processing of the case will take some time. Since the validity of the rate structure for Gandhidham Township Land has expired on 31 March 2020 and since 30 September 2020 is near, this Authority is inclined to extend the validity of the existing rate structure of the Gandhidham township land from the date of its expiry till 31 December 2020 or till the date of effect of notification of the revised lease rentals based on the tariff proposal to be filed by the DPT, whichever is earlier.

4.1. The Land Policy Guidelines of 2010 issued by the Government (based on which the rate structure for Gandhidham Township Land has been fixed in April 2012) stipulates that the lease rentals approved by this Authority shall be escalated by 2% per annum till they are revised by this Authority. The Order passed by this Authority in April 2012 also prescribes a specific condition in this regard. This condition also prevails in the Policy Guidelines for Land Management 2015 issued by the Ministry of Shipping. Since, the existing Schedule of lease rent already prescribes annual escalation @ 2% in the lease rentals till such time the rates are revised by this Authority and in line with the guidelines issued by the Government, the annual escalation @ 2% will continue to apply during the extended validity period of the rate structure for Gandhidham Township Land.

4.2. However, it is to be noted in this regard that the extension of the existing lease rentals with an annual escalation of 2% is only a provisional arrangement to avoid a vacuum in the current scenario. The lease rentals to be fixed for the Gandhidham Township based on the proposal filed by the DPT in this regard will have to be given retrospective effect, as requested by the DPT.

5. In the result, and for the reasons given above, and based on the collective application of mind, this Authority extends the validity of the existing rate structure for Gandhidham Township Land from the date of its expiry till 31 December 2020 or till the date of effect of notification of the revised lease rentals based on the tariff proposal to be filed by the DPT, whichever is earlier.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-3/4/Exty./230/2020-21]